

三三〇

मोहम्मद शाहिद
तचिद
दन्तराख्यात शासन

संस्कृत भाषा

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण दिनांग,
दिल्ली।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग-3

दिनांक 3 / दिसम्बर, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में हरिद्वार जनपद के ब्लॉक नारसन (मंगलौर, सीकर) में महिला डिग्री कालेज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महाद्य

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1142 निसंक./एम.एस.डी.पी./डी.पी.आर./14-15 दिनांक 12.11.2014 का सर्वो ग्रहण करते का कष्ट करे जिसके द्वारा जनपद हरिपुर के खाल नारसन (पंगलौर, सीकर) में महिला डिप्पी कालेज के भवन निर्माण हेतु उपर्युक्त राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवित आगजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के शासनादेश संख्या- 3/20(4)/2013-पीठपी-0-1 दिनांक 19.09.2014 की स्थायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 19.09.2014 के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 को तालिका-3 के क्रमांक-1 पर महिला डिप्पी कालेज के निर्माण हेतु कुल ₹ 333.00 लाख अनुमोदित करते हुए केन्द्रीय ₹ 223.11 लाख में से प्रथम क्रिएश्ट के रूप में ₹ 111.56 लाख की धनराशि अद्युक्त की है।

- उक्त कार्य हेतु यित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसंबर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र यर कार्यदायी संस्था से एमओओयू अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाय। उक्तानुसार निर्धारित समवादपि में कार्य पूर्ण करावार भवन विभाग को हस्तान्तरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार के उक्त सदर्भित पत्र, दिनांक 19.09.2014 हारा प्रदत्त विज्ञा-निर्देशों एवं एम एस ली पौ गाड्ड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उप्रतीराणि निगम हारा एमओओयू में निर्धारित समय के अंतर्गत भवन कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण कर भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाय।

3. परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्बन्ध कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देख लेन्टेज चार्जर्ज से बहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी भेजित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त आवटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका डिट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सहाय अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। कार्य हेतु पूर्व अधमुक्त धनराशि के पूर्व संतोषजनक व्यय विश्वायक आख्या प्राप्त होने पर ही वर्तमान में स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।
5. उक्त धनराशि का व्यय मित्यथला को दृष्टिगत रूपते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। आगणन में प्राविधानित व्यय करने से पूर्व उक्त हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमानुसार 2008 में निहित उपबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। अव्याप्ति अवश्य धनराशि राजकोष में जामा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि अधिप्राप्ति नियमानुसार के अन्तर्गत अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो उच्च शिक्षा विभाग के सुझाव लेखा शीर्षकों/मदों से इसकी पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।
6. आगणन में उत्तिलिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जी दर शिल्पबूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार नाव से की गयी हो की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता की अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
7. एक मुश्त प्राविधानके कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सहाय अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग होस प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुलेप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
10. यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्बन्ध न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानदित गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।
11. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य को समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जी०पी० डब्लू० फार्म ९ की भर्ती के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड प्रसूल किया जायेगा।
12. स्वीकृत उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अधमुक्त करने से पूर्व प्रणवात योजना हेतु भूमि की उपलब्धता की पुष्टि करनी आवश्यक होगी। किसी भी दशा में भूमि उपलब्ध होने से पूर्व उक्त स्वीकृत धनराशि जारी न की जाय।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आद्य-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवाये-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/कन्द्र पुरानिधानियोजनाएँ-01-अत्प्राप्यको हेतु महीं सेक्टोरल विकास योजना के मानक मद-20-संदायक अनुदान/अशादान/राज सहायता के नामे ढाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-265(P)/XVII(3)/2014-15, दिनांक 24 दिसम्बर 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति तथा अलोटमेट आई.डी. संख्या-S1412150282, दिनांक 27 दिसम्बर 2014 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

पुष्टाकन संख्या:— 1140 / XVII-3/14-07(18-MSDP)/2014 : तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयित:—

1. महालेखाकर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, हल्हानी—नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. महाप्रबन्धक, उमप्र० रा० नि० नि० लि०, ई० 34 नेहरू कालोनी देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
7. नोडल अधिकारी, / उपसचिव (एम०एस०डी०पी०) उत्तराखण्ड शासन।
8. जिला अत्यसख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
9. एन आई०सी, सचिवालय परिसर।
10. विनामीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

✓ (सुनीलश्री पांधरी)
संग्रह सचिव।

बाजरा आवास वित्तीय वर्ष - 2014-2015

Secretary, Minority Welfare (S064)

नोटिस नं. 1140/XVII-3/14-07(18-MSDP)/2014

अधिकारी नं. - S14121501282

मनुष्यान संख्या - 015

आवास वर्ष तिथि - 27-Dec-2014

HOD Name - Director Minority Welfare (4132)

केवल शीर्षक	1250 - बाजरा आवासिक संस्थाएँ	00 -												
	800 - इन्हें वित्त	01 - बाजरा आवासिक संस्थाएँ												
	01 - बाजरा आवासिक संस्थाएँ बाजरा आवास वित्त विभाग (60)													
Plan Value:														
<table><thead><tr><th>प्राप्तकर्ता का नाम</th><th>रुपये में जारी</th><th>दर्तावाल में जारी</th><th>वीमा</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) बाजरा आवास वित्त विभाग</td><td>80076200</td><td>16650000</td><td>96726200</td></tr><tr><td></td><td>80076200</td><td>16650000</td><td>96726200</td></tr></tbody></table>			प्राप्तकर्ता का नाम	रुपये में जारी	दर्तावाल में जारी	वीमा	1) बाजरा आवास वित्त विभाग	80076200	16650000	96726200		80076200	16650000	96726200
प्राप्तकर्ता का नाम	रुपये में जारी	दर्तावाल में जारी	वीमा											
1) बाजरा आवास वित्त विभाग	80076200	16650000	96726200											
	80076200	16650000	96726200											
Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -														


(वी.एस.ओ. नोरा)
बाजरा आवासिक
बाजरा आवास वित्त विभाग
राजस्थान शासन